Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, MAR-APR, 2019, VOL- 6/50

ग्रामीण आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका के प्रति दृष्टिकोंण

रिया यादव
(शोध छात्रा– अर्थशास्त्र) जे0 एस0 विश्वविद्यलय; शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

Abstract

क्षे. ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुदानित राशियों से कृषि के सन्दर्भ में भू–विन्यास प्रभावित हुआ है तथा कृषि की दशाएं सुधरी हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्षे.ग्रा. बैंकों की स्थापनाओं से कृषिकों को जरूरतों के अनुसार अनुदानित ऋण किस्तों पर मिल जाने से, परम्परागत खेती न रहकर; कृषि तकनीक विकसित हुई है।बैंकों से लाभान्वित होने से रोजगारों के अतिरिक्त साधन सृजित हुए हैं जिससे प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वित्त पोषण के कारण रोजागरों के अतिरिक्त साधन सृजित हो जाने से लाभान्वितों के रोजगारों में वृद्धि तथा कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि हुई है ऐसा होने से उनकी आय बढ़ी है एवं अन्य व्यावसायिक तथा सहकारी बैंकों की तुलना में क्षे.ग्रा. बैंकों की वित्तीयन प्रणाली विभिन्न सीमाएं होते हुए भी सरल व सहज है। अतः ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय बैंकों की भूमिका सार्थक सिद्ध हुई है।

पारिभाषिक शब्दावलीः *निर्बल (कमजोर) वर्ग, ग्रामीण– आर्थिक विकास, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आर्थिक नियोजन।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

नीतियाँ :

शोध पद्धति : शोध की प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्यों की दृष्टि से वर्णनाात्मक शोध अभिकल्प को चुना गया है। उद्देश्य पूर्ति हेतु 50 निदर्शितों का चयन फिरोजाबाद जनपद (उ0 प्र0) से किया गया है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उद्देश्यः

(1) क्षे. ग्रा. बैंकों से प्राप्त ऋण से होन वाले आर्थिक विकास के प्रति लाभार्थियों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।

(2) प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना।

(3) ग्रामीण निर्बल वर्गों के आर्थिक विकास में क्षे. ग्रा. बैंकों की भूमिका का मूल्यांकन करना।

परिकल्पनायेंः

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीयन प्रणाली सहज तथा सरल है।

(2) विकास योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों एवं उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सहायक हैं।

(3) ग्रामीण निर्बल वर्गों के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें अहम भूमिका का निर्वाह कर रहीं है।

अध्ययन की सीमायें :

प्रस्तुत शोध अध्ययन की सम्भावित सीमायें निम्नवत् हैं –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन उ0 प्र0 के जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल तक ही सीमित है।
2. शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष पूर्ण रूपेण सर्वेक्षित तथ्यों पर आधरित होंगे।

विश्लेषणः क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः दूर सुदूर ग्रामों के कमजोर व निर्बल वर्गों की बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराना था ताकि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक मदद कर अतिरिक्त रोजगार के साधन सुलभ हो सकें।

ग्रामीण स्तरों पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता इसलिये अनुभव की गई क्योंकि सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक (व्यावसायिक) बैंकों जैसी ऋण एजेन्सियॉ ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई दृष्टिकोणों (पहलुओं) से अक्षम थीं उनकी ये अक्षमतायें संक्षेप में निम्नलिखित हैं–

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(1) जहॉ तक प्रबन्धक प्रतिभा, ऋणोपरान्त पर्यवेक्षण और ऋण वसूली का सम्बन्ध है, इन मामलों में सहकारी ऋण व्यवस्था कमजोर है।

(2) वाणिज्यिक बैंक मूलतः नगर उन्मुखी हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में विशेषतः कृषकों के लिये बैकिंग का कामकाज चलाने की दिशा में इन बैंकों को कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, तो पहले उन्हें अपनी पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण को ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ढ़ालना पड़ेगा परन्तु यह काम वाणिज्यिक बैंकों में उच्च वेतन ढ़ॉचा, कर्मचारी व्यवस्था का क्रम तथा उच्च लागत की वजह से सहज तथा जल्दी नहीं हो सकता। इस तरह वे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए इन बैंकों की स्थपनाएं की गयीं।

ग्रामीण आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका के प्रति निदर्शितों के अभिमत निम्नवत् हैं –

प्रश्न 1. ''क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त आर्थिक सहायता से व्यवसायों में वृद्धि होने के साथ–साथ उत्पादकता में वृद्धि हुई है?'' इस प्रसंग में सूचनादाताओं के प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका सं. (1) संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 8.2 : ''क्या व्यवसायों में वृद्धि होने के साथ–साथ उत्पादकता में वृद्धि हुई है?''के सम्बन्ध में सूचनादाताओं के प्रत्युत्तर

क्र0	प्रत्युत्तर	आवृतियॉं	प्रतिशत
1	हॉं	45	90.00
2	नहीं	02	04.00
3	उदासीन	03	06.00
		50	100.00

प्रसंगाधीन तालिका (1) के प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल 50 सूचनादाताओं में से 45(90.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं का यह मानना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभार्थियों के व्यवसायों में वृद्धि होने के साथ–साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। निदर्शितों के इन विचारों से स्पष्ट है कि दैनिक रोजगारों के दिवसों की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संख्या में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि होना, निर्बल वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास का प्रतीक है।

समस्त 50 सूचनादाताओं से अनुसंधित्सु ने पुनः पृथक–पृथक तौर पर प्रश्न किया कि– ''क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से निर्बल वर्गीय परिवारों पर कोई प्रभाव पड़ा है? सर्वेक्षण काल में सभी सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों पर निम्न तालिका सं. (2) संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 2 : ''क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से निर्बल वर्गीय परिवारों पर कोई प्रभाव पड़ा है?''प्रश्न का प्रत्युत्तर

क्र0	प्रत्युत्तर	आवृतियॉ	प्रतिशत
1	आर्थिक दशाएं सुधरी हैं।	46	92.00
2	आर्थिक दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।	00	00.00
3	उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले उत्तरदाता	04	08.00
		50	100.00

प्रसंगाधीन तालिका नं. (2) के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कुल 50 सूचनादाताओं में से 46(92.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह पृथम दृष्टया ही स्वीकार किया है कि क्षे.ग्रा. बैंकों से विकास के सन्दर्भ में लाभान्वित होने से निर्बल वर्गीय परिवारों की सामाजिक–आर्थिक दशाएं सुधरी हैं। प्रति पक्ष में उत्तर प्रदान करने वाला एक भी सूचनादाता नहीं पाया गया है। मात्र 04 (08.00 प्रतिशत) सूचनादाता उदासीन अभिमत दर्शाने वाले पाए गए हैं जो नगण्य (अत्यन्त न्यून) हैं। इन प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि– ''क्षे.ग्रा. बैंकों की वित्तीयन प्रणाली से लाभान्वित होने से निर्बल वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशाएं गुणात्मक रूप से सुधर रही हैं।''

निष्कर्षः

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(1) सूचनादाताओं के अनुसार क्षे. ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुदानित ऋणों से कृषि के सन्दर्भ में भू–विन्यास प्रभावित हुआ है तथा कृषि की दशाएं सुधरी हैं।

(2) सूचनादाताओं का अभिमत है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्षे.ग्रा. बैंकों की स्थापनाओं से कृषिकों को जरूरतों के अनुसार अनुदानित ऋण किस्तों पर मिल जाने से, परम्परागत खेती न रहकर; कृषि तकनीक विकसित हुई है।

अतः परिकल्पनायें सत्य एवं सार्थक पायी गयी हैं।

संदर्भ

पाठक के0 पी0 ; रोल ऑफ आई.आर.डी.पी. इन दि रूरल इकोनोमिक डवलपमेन्ट ऑफ यू.पी.; ए केस स्टडी ऑफ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, पब्डिस्ड पी. एच–डी थीसिस, रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर 2015

सिंह आर.के.; कृषि तथा ग्रामीण आर्थिक विकास की समस्यायें, मीतल प्रकाशन, मथुरा, 2007 पृ. 179

कुरैजा (भारतीय ग्रामों का बदलता परिदृश्य ; धर्मयुग पत्रिका जयपुर, अप्रैल, 11 (अंक – 3) 2007:30

पान्सियन जे.ए.; नेशनल डबलपमेन्ट : एन इकोनोमिक कन्ट्रीब्यूशन, दि दाम्यु पब्लिकेशन्स, मारटन, न्यूयार्क, 2008 पृ.106

द्विवेदी के.डी. तथा अन्य; भारतीय आर्थिक विज्ञान समीक्षा, विकास का अर्थशास्त्र, बी.एच.यू. वाराणसी (विश्वविद्यालय प्रकाशन) 2008 पृ.6

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies